कपड़े के दाम

*1110. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कपड़ा मिलों ने वित्त मंत्री के 27 फरवरी, 1965 के बजट भाषण के बाद कपड़े के दाम बढ़ा कर उत्पादन शुल्क में की गई कमी को खत्म किया है जिसके फलस्वरूप कपड़े के फुटकर दाम बढ़े हैं ;

(ख) ऐसे मिलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) उत्पादन शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके, क्या इसके लिए कोई उपाय किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ङ). नियंत्रित किस्मों के कपड़ों के मिल से निकलते समय के मूल्य और खुदरा मूल्य कानूनी तौर पर निर्धारित किये जाते हैं, और किसी मिल या बिक्रेता को इन मूल्यों में वृद्धि करने की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार उत्पादन शुल्क भी कानूनी तौर पर लिया जाता है और उसे भी बदला नहीं जा सकता। इसलिये किसी मिल द्वारा नियन्त्रित कपड़े के मूल्य बढ़ा कर उत्पादन शुल्क में की गई कमी को खत्म करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बजट में घोषित की गई राहतों के फलस्वरूप मोटे तथा मध्यम दर्जे के नियन्त्रित किस्म के कपड़ों के मूल्यों में 1 मार्च, 1965 से बजट पूर्व के नियन्त्रित मूल्यों की अपेक्षा 2 से 10 प्रतिशत तक की कमी हो गई है। इस कमी का हिसाब लगाते समय रुई के भावों में हुई सीमान्त वृद्धि का भी लेखा किया गया है।

Eviction of Refugees from Railway Land in Assam

*1111. **Shri Priya Gupta:**
Shri Alvares:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Hem Barua:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the North-East Frontier Railway has passed orders to evict about 1500 refugee families settled on Railway land for the last fifteen years at Pandu, Gauhati, Narangi and Amingaon areas in Assam;

(b) whether the Railway administration has permitted settlement on conditions that this would not interfere with construction programme of Railway lines;

(c) whether some of these families are employed in Railway service, while others are having small business in the vicinity catering to the needs of the Railway colony in various markets;

(d) whether the "Settlers Association", Pandu has represented the case to Government, if so, Government's reaction thereto; and

(e) the reason for the decision to evict these refugees without providing alternative accommodation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No, Sir; Notices for vacation of Railway land have been served on only 546 encroachers at Pandu. Out of these, 466 families encroached on Railway land after 1961. The remain-

ing 80 families have been squatting for a longer period.

(b) No.

(c) No.

(d) To accommodate the affected families and to avoid hardship to certain families already settled on the land, certain plots of land were excluded from the area under Acquisition by the Railway.

(e) The land encroached upon is required for urgent Railway development works. 466 families have encroached after 1961 and remaining 80 families were offered some compensation at the time of acquisition and asked to move to the excluded areas mentioned above.

कोयले का निर्यात

*1112. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है जो कोयले का निर्यात बढ़ाने के काम की जांच करेगी और इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देगी ;

(ख) यदि हां, तो कोयले का निर्यात बढ़ाने के लिए समिति ने अब तक क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) उनके फलस्वरूप कितनी मात्रा में कोयले का निर्यात बढ़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कोयले के अध्ययन दल के नाम से पुकारी जाने वाली समिति की अभी तक दो बैठकें 22 फरवरी, 1965 तथा 12 अप्रैल, 1965 को हो चुकी हैं और यदि सम्भव हुआ तो यह अपना प्रतिवेदन तीन मास के भीतर प्रस्तुत कर देगी ।

Export Credit Guarantee Scheme

*1113. **Shri P. R. Chakraverti:**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign exchange to the extent of Rs. 15 crores available to finance manufacturers/exporters and to promote the country's exports under the scheme being operated by the Export Credit and Guarantee Corporation has remained unutilised;

(b) whether the reluctance of Indian exporters to utilise this revolving foreign exchange credit is due to unfavourable terms; and

(c) if so, the advice tendered to the exporters and the State-owned Corporations to make suitable adjustments so as to compete more effectively in the world market?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). The Scheme of 'Revolving Foreign Exchange Credits for Exporters' has been in operation for about six months now. Various commercial banks participating in the scheme have indicated their readiness to arrange for lines of credit in foreign exchange amounting to about Rs. 15 crores. These have not yet been finalised and they are in various stages of negotiation Under the present procedures, every line of credit should have the approval of the Reserve Bank of India. So far the Reserve Bank of India has given its approval for lines of credit of the value of Rs. 2.4 crores.

Only two applications have so far been received and they have been cleared.